रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 5 सितम्बर, 2007 / 14 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अगस्त, 2007

सख्याः एफ.डी.एस.–ए (3)–2/2003.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में लिपिक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से सलंग्न् उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, लिपिक, वर्ग– III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हागें।

2. **निरसन और व्यावृतियां.–** (1) अधिसूचना संख्याः 1–15/69–एफ एण्ड एस, तारीख 11 दिसम्बर,1973 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर यथा सशेधित दी हिमाचल पदेश फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट क्लास– III सर्विस (रिक्रूटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कन्डीशन्ज आफ सर्विस) रूल्स, 1973 का, एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये लिपिक के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम–2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
परमिन्द्र हीरा माथुर,
अति0 मुख्य सचिव।

———————

उपाबन्ध –''क''

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, लिपिक, वर्ग– III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : लिपिक

2. पदों की सख्या : 94 (चौरान्नवे) ।

3. वर्गीकरण : वर्ग–– III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं ।

4. वेतनमान : (विस्तृत रूप में दिया जाए) 3120–100–3220–110–3660–120–4260–140–4400–150– 5000–160– 5160 रूपए (प्रारम्भिक आरम्भ 3220 / – रूपए) के साथ

5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियां को लागू नहीं होगी, :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसचित जन–जातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तिओं के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छुट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञये है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमले न से पर्वू सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृदं को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिये यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–

अनिवार्य अर्हताए :

(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विशविद्यालय से द्वितीय श्रणेी में दसवीं या 10+2 परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष ।

(2) अग्रेंजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टकंण में 25 शब्द की न्यूनतम गति रखता हो।

(ख) वांछित अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही :

आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसी कि स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थ।नातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता .– (1) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या सविदा के आधार पर।

(2) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या सविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, या स्थानातरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा.– वर्ग– **IV** कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास हो या जो दसवीं (अग्रेंजी के एक विषय सहित) हिन्दी (रत्न) पास हों आरै जिनका पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रडे में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पाचं वर्ष का सयुंक्त नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु ऐसे वर्ग–**IV** कर्मचारी, जिनकी प्रेान्नति / नियुक्ति करूणामूल क आधार पर हुई हो तथा जो नियुक्ति के समय दसवी पास (तृतीय श्रेणी) या दसवीं (केवल अग्रेंजी विषय सहित) हिन्दी (रत्न) पास शैक्षिक योग्यता रखते हो, वरिष्ठ सहायक के पद के लिए आगामी प्रोन्नति के लिए तब तक विचार करने हेतु पात्र नही होंगे जब तक कि वे उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7 में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त नही कर लेते।

परन्तु ऐसे पात्र वर्ग–**IV** कर्मचारियों को कार्यालय प्रक्रिया, टकंण और शब्द प्रसंस्करण में एचआइपीए (हिपा) सोसायटी के माध्यम से संस्था में या उनके अपने अपने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित अथ्यर्थि प्रोन्नति के योग्य होगा। प्रशिक्षण केवल एक बार ही होगा, परन्तु समय समय पर उन्हे परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा जो पहली बार परीक्षा पास करने में असमर्थ रहते है।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग–**IV** कर्मचारियों की,,उनके अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

(1). प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि काई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्तं के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी,, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगें:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगें ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी,, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12 यदि विभागीय प्रदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.– जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13 भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.– जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14 सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.– किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति हिमाचल लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका यथास्थिति स्तर / पाठयक्रम आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :

(I) संकल्पना : (क) इस पोलिसी के अधीन खाद्य, नागरिक आपुर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदात्मक लिपिक को सरकारी सेवा (जाब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

II. संविदात्मक उपलब्धियां :– संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 4830 / –रूपए की दर से समेकित नियत सविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई रकम दये नहीं होगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकत में 100 / –रूपए की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

III. नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः– निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा

IV. चयन प्रक्रियाः– संविदा नियुक्ति की दशा मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

V. संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः– जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, द्वारा गठित की जाए।

VI. करार :– अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

VII. निबन्धन और शर्तें :– (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को, 4830 / – रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 / – रूपए की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त लिपिक की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड) कार्यालयाध्यक्ष (हैड आफ आफिस) के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त लिपिक कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार की संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्रधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त लिपिक का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

VIII. नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.– इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में लिपिक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16 आरक्षण .–सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा .–लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति.–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

———————

उपाबन्ध–''ख''

.....(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती .....पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात **प्रथम पक्षकार** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया है।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को .....के रूप में लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिये सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार .....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में .....के रूप में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में नियमितिकरण सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त (पदनाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा / होगी। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नही होगा / होगी। प्रसूति अवकाश केवल प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 के अनुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तब्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान(समापन्न) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त (पदनाम) कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नही होगा / होगी।

7. संविदा पर नियुक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि, अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ व ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Departmen Notification No. Fds-A(3)-2/2003 dated 13-08-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 13th August, 2007

No. FDS-A(3)-2/2003.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III, (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Clerk, Class-III, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Food & Supplies Department, Class-III, Service (Recruitment, Promotion and Certain conditions of Service)Rules, 1973 notified vide notification No. 1-15/69-F&S, dated 11-12-1973 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Clerk.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed, under rule-2(I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
PARMINDER HIRA MATHUR,
Addl. Chief Secretary.

———

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK,(CLASS-III, NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS , HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post : Clerk

2. Number of Post(s) : 94 (Ninety four).

3. Classification: Class –III (Non-Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of Pay : (Rs. given in expanded ratation) Rs.3120-100-3220-110-3660-120-4260 140-4400-150- 5000-160-5160 (with initial start of Rs. 3220/-

5. Whether Selection Post or non selection post : Non –Selection

6. Age for direct recruitment : Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis; Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age-concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits:

Essential Qualifications: (i) Should have passed Matriculation with IInd division or 10+02 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University.

(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.

Desirable Qualifications: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of the promotee(s):

Age : Not applicable.

Educational: Qualifications: Yes, as prescribed in column No. 11.

9. Period of Probation, if any : Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods :

(i) 90% by direct recruitment or on contract basis

(ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promo-tion/deoutation/transfer is to be made : By promotion from amongst the class-IV officials who are matric or Hindi (Rattan) with Matric(English as one of the subject) and also possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

Provided that the incumbents of the post of Class-IV officials so promoted or appointed on compassionate grounds having the educational qualification of Matric pass(3rd Division) or Matric(in English only) with Hindi Rattan pass at the time of such appointment, shall not be considered to be eligible for their next promotion for the post of Senior Assistant until they possess th minimum educational qualification as prescribed for direct recruitment in Col. No. 7 above..

Provided that the 2 months training to the eligible Class-IV persons will be given in office procedure, type-writing and word processing through HIPA Society either at the Institue or at their respective District Training Centres. Trained candidates will be eligible for promotion. Training will be held only once but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those who are unable to pass the test in one go.

For the purpose of promotion a combined seniority of Class-IV employees on the basis of length of service without disurbing their cadre-wise inter-seseniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :-

(a) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular ppointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition? As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under whichthe Himachal Pradesh Public Servicec Commission is to be consulted in making recruitment : As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment : A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment : Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voice test if the Himachal Pradesh Public Servicec Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15(A). Selection for appointment to the post by contract appointment.

(I). CONCEPT:— (a)Under this policy, the Clerk Class in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh will be engaged on contract basisinitially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Director, Food, Civil Supplies & Consumer affairs, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contractual Clerk so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(II). CONTRACTUAL EMOLUMENTS: —The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4830/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). No amount will be paid for absence period. An amount of Rs. 100/- as increase in contractual amount for second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III). APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh will be Appointing and Affairs, Himachal Pradesh will be Appointing and Disciplinary Authority.

(IV). SELECTION PROCESS:— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(V). COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(VI). AGREEMENT:— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B, appended to these rules.

(VII). TERMS & CONDITIONS:— (a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 4830/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ Rs. 100 /- per month for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. shall be given.

(b) The service of the contractual Clerk will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contractual Clerk will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Clerk. He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from duty without the approval of the Head of the office shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual Clerk will not be entitled for any contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a Clerk appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. In case of women candidates, pregnancy beyond 12 weeks will render her temporarily unfit untill the confinement is over. The women candidate should be re examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract Clerk shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular officials.

(VIII). RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:— The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as Clerk in the department at any stage.

16 Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17 Departmental Examination : Not applicable

18 Power to relax : Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs

This agreement is made on this _____day of_____in the year_____Between Sh./Smt.----------S/o/D/oShri---------- R/O_____Contract appointee (here-in-after called the First Party), and the Governor, Himachal Pradesh through Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs , Himachal Pradesh (here-in after the Second Party).

Whereas, the Second Party has engaged the aforesaid First Party and the First Party has agreed to serve as a ----------on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as ----------for a period of 1 year commencing on day of_____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the First Party with Second Party shall ipso-facto stand terminated on the information and notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the First Party will be ----------per month.

3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual ---------- (Name of the post)will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual-----(Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer

shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual ----------(Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of Contractual appointee on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at minimum of the pay scale.

10. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PARESENCE OF WITNESS:
1_____
_____
_____
(Name and Full Address)

2_____
_____
_____
(Name and Full Address)

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1_____
_____
_____
(Name and Full Address)

2_____
_____
_____
(Name and Full Address)

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st September 2007

No. Per (AR) F (7) 2/98-Vol.I.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh hasconstituted the Himachal Pradesh State Information Commission vide Notification No. Per (AR) F (7) 2/98-Vol.I dated 4th February 2006.

And whereas Shri Surjit Singh Parmar, IAS (Retd.) has been included as State Information Commissioner, Himachal Pradesh in the H.P. State InformationCommission vide Notification No. Per (AR) F (7) 2/98-Vol.I dated 28th June 2007 and Shri Surjit Singh Parmar, made and subscribed an oath under sub-section (3) of section 16 of the Right to Information Act, 2005 on 2nd July, 2007.

And whereas section 16(5) of the Right to Information Act, 2005 provides that the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the State Information Commissioner shall be the same as that of Chief Secretary of the State as amended from time to time and conditions of service relating to traveling allowance, provision of conveyance facilities, sumptuary allowance, medical facilities and such other conditions of service as are, for the time being, applicable to the Chief Secretary of the State Government.

Now therefore, Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that the salary and allowances and other terms and conditions of Shri Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner, Himachal Pradesh shall be as contained in the *Annexure*.

By order,
S.VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

———

Annexure

TERMS AND CONDITIONS OF SHRI SURJIT SINGH PARMAR, STATE INFORMATION COMMISSIONER HIMACHAL PRADESH

1. Tenure :

Shri Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner shall hold office for a term of 5 (five) years w.e.f. 02.07.2007. Shri Surjit Singh Parmar State Information Commissioner shall not be eligible for reappointment. However, he may be appointed as the Chief Information Commissioner in accordance with the provisions of the Act.

2. Pay :

He shall draw a pay of Rs. 26,000 p.m. (fixed) (Basic pay Rs. 26,000/- plus Dearness Pay Rs. 13,000/-) Since he is in receipt of pension under AIS (Rules), his salary as State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension (including commuted portion of pension).

3. Sumptuary Allowance:

A monthly sumptuary allowance of Rs.4,000/- [Four thousand rupees] per month shall be admissible to Shri Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner.

4. Provident Fund :

He shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund (Central Services). Since he was a member of the India Administrative Service before taking over as State Information Commissioner, Himachal Pradesh, he shall continue to subscribe to the Provident Fund to which he was subscribing before his appointment as the State Information Commissioner.

+

5. Leave :

Shri Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner shall be entitled for leave in accordance with the provisions of AIS (Rules). The power to grant or refuse leave to the State Information Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him shall vest in the Chief Information Commissioner.

6. Accommodation :

Sh.Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner shall be entitled to the use of an official residence in accordance with the rules prescribed for Chief Secretary. Where the State Information Commissioner does not avail himself of the use of an official residence, he may be paid every month an allowance equal to that payable for the purpose to the Chief Secretary of the State Government.

7. Medical facilities :

Sh.Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner and the members of his family shall be entitled to such facilities for medical treatment and for accommodation in hospitals as prescribed for the Chief Secretary from time to time.

8. Conveyance allowance :

Sh.Surjit Singh Parmar, State Information Commissioner shall be entitled to a staff car and the actual consumption of fuel.

9. TA/DA on Tour/LTC :

He shall be entitled to Travelling Allowance/Daily Allowance as applicable to the Chief Secretary and Leave Travel Concession once in a year, for himself, spouse and dependent members of his family to any place in India.

10. Administrative & other Residuary Matters:

Administrative matters relating to terms and conditions of service of the State Information Commissioner with respect to which no express provision has been made shall be as applicable to the Chief Secretary.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th August, 2007

No. UD-A(3)14/2005.—In continuation of this department's notification of even number dated 10-1-2007, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the H.P. Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (Act No.22 of 1971), is pleased to appoint Sh. N.L.Sharma, HAS, Land Acquisition Officer, PWD, South Zone, Shimla, Himachal Pradesh as Collector to perform the functions of the Collector under the Act and to dispose off all the cases of encroachment on Municipal land and forest land as well in the area of Municipal Corporation Shimla.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 2 अगस्त, 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–4 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम,1894(1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सीसी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बूरांवाला, तहसील कसौली तथा मुहाल कुजांहल, तहसील नालागढ, जिला सोलन, हि0 प्र0 में 132 के0 वी0 सबस्टेशन झाडमाजरी से रामास्टील लि0 मौजा बटड़े तक 132 के0वी0 लाईन तथा 132 के0वी0 डब्बल सर्कट टावर द्वारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही ं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैकं भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर		रकवा (बीघा में)
सोलन	कसौली	बूरांवाला	54 / 1		0–4
			83 / 1		0–4
	नालागढ़	कुजांहल	51 / 1		0–4
			23 / 1		0–4
		कुल कित्ता–	4	कुल रकबा–	0–16 बीघा

आदेशद्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

———

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 4 अगस्त, 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–23 / 2006.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज फोजल पावर प्राईवेट लिमिटेड, सी–25, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली जो कि भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मेहा तथा दवाड़ा, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में फोजल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियमए 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधी के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता–एवं– उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
कुल्लू	कुल्लू	मेहा	809	0–01–20
			811	0–00–14
			822	0–01–40
			823 / 2	0–02–15
			815 / 1	0–00–78
			830	0–28–93
			823 / 1	0–07–28
		किल्ला–	7	रकबा– 0–41–88
		दवाड़ा	757/1	0–02–74
			756/1	0–01–48
			706/1	0–03–92
			710 / 1	0–00–92
			705 / 1	0–01–56
			711 / 1	0–04–45
			700 / 1	0–01–38
			852 / 1	0–02–60
			848 / 1	0–02–20
			846	0–29–63
			847	0–01–00
			832	0–30–26
			834	0–01–20
			838	0–02–56
			839	0–02–70
			845	0–01–17
			731	0–01–02
			732 / 1	0–00–42
			735 / 1	0–01–00
			734 / 1	0–02–10
			762 / 1	0–01–21
			766 / 1	0–07–42
			738 / 1	0–00–55
		किल्ला–	23	रकबा– 1–03–49
		कुल किल्ला–	30	कुल रकबा– 1–45–37

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

———

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 4 अगस्त, 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–6 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लियूंगड़ी ब्राहम्णा तथा खारसी कनैता, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 में 132 के0 वी0 (द्विपथ) संचार लाईन खारसी से बागा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गावं	खसरा नम्बर	रकवा (बीघा में)
बिलासपुर	सदर	लियूंगडी़ ब्राहम्णा	156/49/2/1	0–4
			156/49/2/2	0–7
		खारसी कनैता	196/1	0–3
			123/1	0–7
			6/1	0–7
			253/1	0–4
		कुल कित्ता–	6 कुल रकबा–	1–12 बीघा

आदेशद्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

———

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 25 अगस्त 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–35 / 2006.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल रागुरा, कशमीर,दुनी, कल्पा, सरयों रोधी ढाकयों, तहसील कल्पा, मुहाल अकपा, जंगी, कुटंग तहसील मोंरग, मुहाल सपिलों, नमकलंग, कानम(निचला), गयमिल, दनपोछे, तहसील पूह, मुहाल कुटानों चोलिंग, टापरी तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 मे 220 के0 वी0 D/C सचं ार लाईन काशंग से भावा व 22 के0 वी0 लाईन 66 के0 वी0 टावर पर अकपा से पूह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)	
किन्नौर	कल्पा	रागुरा	532/154/1	0–03–24	
		कशमीर	19/1	0–01–53	
			20/1	0–00–30	
			23/1	0–01–69	
			175/1	0–00–39	
			937/1	0–03–60	
			किल्ला– 5	रकबा– 0–07–51	हैक्टेयर
9					
		दुनी	199/1	0–00–36	
			2001 / 1	0–01–30	
			214 / 1	0–01–41	
			231 / 1	0–00–48	
			496 / 1	0–00–40	
			497 / 1	0–01–24	
			498 / 1	0–00–33	
			502 / 1	0–01–10	
			543 / 1	0–01–80	
			547 / 1	0–01–95	
			किल्ला– 10	रकबा– 0–10–37	हैक्टेयर
		कल्पा	1299 / 1072 / 1	0–01–26	
			1302 / 1074 / 1	0–00–56	
			किल्ला–2	रकबा– 0–01–82	हैक्टेयर
		सरयो	621 / 463 / 1	0–01–20	
			390 / 1	0–00–91	
			391 / 1	0–01–26	
			394 / 1	0–00–39	
			614 / 343 / 1	0–01–66	
			किल्ला– 5	रकबा– 0–05–42	हैक्टेयर
		रोघी	466 / 308 / 1	0–01–32	
		ढाकयों	262 / 1	0–03–35	
			265 / 1	0–00–38	
			किल्ला– 2	रकबा– 0–03–73	हैक्टेयर
	मोंरंग	अकपा	742 / 601 / 1		0.02.28
			368 / 1	0–01–76	
			369 / 1	0–00–80	
			किल्ला– 3	रकबा– 0–04–84	हैक्टेयर

		जंगी	635 / 1	0–02–56	
			603 / 1	0–01–28	
			532 / 1	0–01–96	
			किल्ला– 3	रकबा– 0–05–80	हैक्टेयर
		कुटंग	357 / 336 / 311 / 1	0–02–56	
	पूह	सपिलो	1423 / 1319 / 1	0–02–56	
			1232 / 1	0–02–25	
			680 / 1	0–02–56	
			किल्ला– 3	रकबा– 0–07–37	हैक्टेयर
		कानम(निचला)	188 / 1	0–00–99	
			414	0–00–55	
			415	0–00–64	
			667 / 1	0–02–56	
			किल्ला– 4	रकबा– 0–04–74	हैक्टेयर
		गयामिल	214 / 43 / 1	0–02–56	
			44 / 1	0–02–56	
			किल्ला– 2	रकबा– 0–05–12	हैक्टेयर
		दनपोछे	775 / 106 / 1	0–02–56	
		लाबरगं	525 / 65 / 1	0–02–38	
			150 / 1	0–00–91	
			153 / 1	0–00–66	
			किल्ला– 4	रकबा– 0–04–55	हैक्टेयर
	निचार	कुटानों	472 / 1	0–04–94	
			640 / 471 / 1	0–00–60	
			517 / 1	0–01–60	
			518 / 1	0–01–45	
			किल्ला–4	रकबा– 0–08–59	हैक्टेयर
		चोलिंग	246 / 1	0–04–00	
			336 / 221 / 1	0–02–25	
			330 / 321 / 203 / 1	0–02–25	
			किल्ला–3	रकबा– 0–08–50	हैक्टेयर
		टापरी	219 / 1	0–02–04	
			222 / 1	0–01–92	
			271 / 1	0–02–42	
			397 / 1	0702–96	
			439 / 1	0–01–82	
			किल्ला–5	रकबा– 0–11–16	हैक्टेयर
		कुल	किल्ला–60 कुल	रकबा– 1701–76	हैक्टेयर

आदेशद्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 25 अगस्त 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)-5/2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः फाटी दुसाहड़ कोठी वनोगी, उप तहसील सैजं , जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–।।। वन विभाग अतिथि गृह से मनहम तक सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए क उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
कुल्लू	सैंज फाटी	दुसाहड़ कोठी वनोगी	1203/1/2/1	0-05
			1223/1	1-02
			1226/1	0-18
		कुल कित्ता– **3** कुल	रकबा– **2.05**	बीघा

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 25 अगस्त 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)-9 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः फाटी मन्यासी व दुसाहड़ कोठी वनोगी, उप तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–।।। (सैंज वाई पास रोड़ आर0डी0 2495 मी0 से 3028 मी0) हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
कुल्लू	सैंज	फाटी मन्यासी कोठी वनोगी	3 / 1	0–10–9
			4 / 1	1–16–13
			17 / 2 / 1	1–7–8
			1861 / 1804 / 18 / 1	1–3–2
			1869 / 22 / 1	2–5–0
			1868 / 22 / 1	1–5–4
			22 / 1 / 1	2–4–6
			26 / 1	0–4–13
			किल्ला– 8	रकबा– 10–16–15 बीघा
		फाटी दुसाहड़ कोठी वनोगी	168 / 2 / 1	0–12–11
			किल्ला– 1	रकबा– 0–12–11 बीघा
			कुल किल्ला– 9	कुल रकबा– 11–9–6 बीघा

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

बहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 25 अगस्त 2007

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–19 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल पशगांव, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में गानवी जल विद्युत परियोजना स्टेज –।। की सड़क एवं इन्टेक एरिया के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा पद्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गावं	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
शिमला	रामपुर	पशगांव	503	0–03–61
			602	0–14–55
			601	0–08–61
			598	0–20–93
			591	0–38–72
			737 / 2 / 2 / 1	0–00–52
		कुल कित्ता–6	कुल रकबा–0–86–94	हैक्टेयर

आदेशद्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd August, 2007

No.HHC/Admn.16 (21)75-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(v) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment and Control) Rules,1996 is pleased to appoint Sh. Kartik Kumar, Miss Nidhi Sharma, Sh. Karam Chand Sankhyan and Sh. Rakesh Raghuvanshi, Advocates of H.P. High Court, as Oath Commissioners for the High Court, Shimla with effect from 11.8.2007 for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd August, 2007

No. HHC/Rules/22(24)/83-II.—In exercise of the powers conferred by Section 139(b) of code of Civil Procedure, 1908 readwith section 29 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and section 297 of Code of Criminal procedure, 1973 the High Court of Himachal Pradesh makes the following rules regarding appointment and control of Oath Commissioners:—

1. *Short title.*—These rules shall be called "The Himachal Pradesh Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007."

2. *Commencement.*—They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Definition.*— (a) "Advocate" means an Advocate enrolled as such under the Advocates Act, 1961 and practising in a Court of law.

(b) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh.

(c) "District and Sessions Judge" means the District and Sessions Judge of a particular Civil and Sessions Division in the State of Himachal Pradesh.

(d) "Administrative Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal.

(e) "Registrar" means and includes the Registrar General, Registrar (Rules), Registrar (Vigilance), Registrar (Inspection) of the High Court of Himachal Pradesh and the Registrar, Himachal Pradesh Administrative Tribunal at Shimla."

(f) All other words and expressions used in these rules, but not defined therein shall have the meanings respectively assigned to them in the Civil Procedure Code, 1908 Himachal Pradesh Courts Act , 1976 and the Code of Criminal Procedure , 1973.

3. *Strength of Oath Commissioners at each place.*—The number of Oath Commissioners for the High Court, Administrative Tribunal as well as at each District, Sub-Divisional and Tehsil / Sub Tehsil headquarters shall be determined by the High Court from time to time.

4. (i) Mode of "When a vacancy of oath commissioner is Appointment likely to occur in the High Court, the Registrar General shall invite applications atleast 45 days before the expiry of the term of the sitting Oath Commissioner(s) for filling up the vacancy from amongst theAdvocates of the High Court Bar in the prescribed form (Appendix-A)"

(ii) When a vacancy of Oath Commissioner is likely to occur within his jurisdiction the District and Sessions Judge shall invite applications, in respect of the Sessions Division headquarters direct, while in case of a place other than the Sessions Division headquarters through the Civil Judge (Senior Division)/Civil Judge (Jr. Division) of the area concerned, at least 45 days prior to the expiry of the term(s) of serving Oath Commissioner(s) for filling the vacancy from amongst the Advocates of the local Bar in the prescribed form annexed as Appendix-A to these Rules.

(iii) When vacancy of Oath Commissioner is likely to occur in the Administrative Tribunal at Shimla, the Registrar, Administrative Tribunal shall invite applications atleast 45 days before the expiry of the term of the serving Oath Commissioner(s) for filling up the vacancy from amongst the advocates practising in the Administrative Tribunal on the prescribed form annexed as Appendix-A to these Rules.

(iv) The District and Sessions Judge and the Registrar Administrative Tribunal shall scrutinize the applications received from desirous candidates and in case an application is found to be not in order, the same shall be returned to the applicant with objections in writing and such applicant may file the application afresh, if he so desires, within the time to be specified by the District and Sessions Judge

(v) In case the application(s) are found in order or are so found after removal of objections within the stipulated period, the District and Sessions Judge or Registrar Administrative Tribunal, as the case may be, shall forward the applications to the Registrar General of the High Court atleast 10 days prior to the expiry of the term of the Oath Commissioner alongwith his recommendations, if any, with the following information relating to the applicant:—

(a) Standing at the Bar;

(b) Whether lady/Scheduled Caste/ Scheduled Tribe OBC/physically handicapped;

(c) Reputation of the applicant with regard to his integrity and honesty;

(d) Whether he has acted previously as Oath Commissioner, if so, the period thereof?

(e) Whether he indulges in any malpractice like touting etc.?

(f) General behaviour with public.

(vi) The Chief Justice in his discretion may appoint such number of persons as Oath Commissioners out of the applicants found eligible for such appointment as may be required.

(vii) Appointment shall ordinarily be made for a period of two years and preference shall be given to the new entrants at the Bar, subject to the fulfilment of requisite qualifications as prescribed in the Rules.

5. The Oath Commissioner immediately on his appointment shall notify on the Court notice board the address of his residence and the office where he/she shall be available to the public after seeking permission of the Presiding Officer of that Court.

6. *Formalities to be observed by the Oath Commissioner while attesting.*—While attesting an affidavit, the Oath Commissioner shall observe the following legal formalities:—

(i) The Oath Commissioner shall administer oath/solemn affirmation to the deponent in vernacular, if he is not conversant with English. In case the deponent knows English, the oath may be administered in English or vernacular.

(ii) Contents of affidavit shall be sworn /affirmed by the deponent in the presence of the Oath Commissioner.

(iii) The Oath Commissioner shall, at the time of attestation, read over and explain the contents of affidavit to the deponent in vernacular, if he does not understand English and if the deponent understands English, he shall certify having read over the contents of the affidavit to the deponent by affixing his stamp to be maintained on prescribed form annexed as Appendix-'B' to these Rules.

(iv) In case the Oath Commissioner does not personally know the deponent, he shall get him identified by a person known to him. The Oath Commissioner shall affix a stamp on the prescribed form annexed as Appendix-'C' to these Rules about identification below the stamp as annexed at Appendix-'B' and get signature of the identifier at the relevant place.

(v) The Oath Commissioner shall thereafter append a certificate to the affidavit attested by him in the prescribed form annexed as Appendix- 'D' to these Rules.

(vi) The Oath Commissioner shall affix his seal indicating his full name in capital letters and then put his signature over the seal on the affidavit, which entry shall be made in the register as required under rule 8 below, and he shall append his signatures on every page of the petition supported by such affidavit. The seal shall be of one inch diameter with full name in capital letters and designation of the Oath Commissioner in the outer circle and the word "Advocate with name of place inscribed in the centre within the inner circle alongwith Serial Number, date and time of attestation.

7. *Fee for attestation of Affidavits.*—(a) Fees for attesting affidavits and Administration of oath or affirmation shall be as under:—

(i) At the Court house or residence of the oath Commissioner for every affidavit, oath or affirmation ……..Rs. 10/-

(ii) Within a radius of 8 kms. from the court house, office or residence of the oath Commissioner for the first affidavit ….. …….. Rs.25/-(plus actual bus fare)

For every additional affidavit, oath or affirmation at the same time and place… …….Rs. 10/-

(iii) Beyond 8 Kms. for the first affidavit,Oath or affirmation ……Rs. 50/-plus (actual bus fare).

For every additional affidavit etc. at the same time and place.Rs.10/-.

(b) The above charges will be in addition to any stamp duty payable on the affidavit under Schedule-I, Article-4 of the Indian Stamp Act, 1899.

(c) A written receipt for the amount of fee received shall be given by the Oath Commissioner to the deponent. The receipt shall be on a printed form annexed as Appendix-E to these Rules consisting of foil and counterfoil, the foil being handed over to the person paying the fees and the counter-foil being kept by the Oath Commissioner for records.

8. *Register of affidavits.*—All affidavits attested by an Oath Commissioner shall be entered in a register to be maintained on the prescribed form annexed as Appendix-F to these Rules.

9. *Periodical Inspection of the Registers maintained by Oath Commissioner*.—(i) Inspection of the registers of Oath Commissioners shall be conducted quarterly at the headquarters of the District and Sessions Division by the Civil Judge(Senior-Division)and at the Sub Divisional headquarters by the Civil Judge and if there are more than one Civil Judges, then by the senior most Civil Judge. A copy of the inspection note shall be sent to the respective District and Sessions Judge by the Inspecting Officer by the 10th of the month and the consolidated statement of the Division shall be sent by the District and Sessions Judge to the Registrar General of the High Court by the 15th of the month following the month of inspection.

(ii) Inspection of registers of Oath Commissioners at the High Court shall be conducted quarterly by the Registrar or his nominee and in the Administrative Tribunal by the Registrar and the report shall be placed before Hon'ble the Chief Justice for perusal and orders,

(iii) While inspecting the working of the Oath Commissioners and preparing the report thereof, the Inspecting Officer must inspect and specifically report about the compliance of the following instructions by the Oath Commissioners:—

(a) Whether the Oath Commissioner is maintaining the register of affidavits on the prescribed form,

(b) Whether the columns of the register are filled in properly giving all the requisite details and are signed by the deponent, identifier and the Oath Commissioner?

(c) Whether the Oath Commissioner is issuing receipts for the amount of fees received on prescribed printed form?

(d) Whether the Oath Commissioner has attested any such affidavit, which he could not attest ?

(e) Whether the fee charged by the Oath Commissioner is in accordance with the fee prescribed under these Rules?

(f) Whether the Oath Commissioner is giving date, time and number while attesting the affidavits?

(g) In case the Oath Commissioner is found consistently committing the mistakes, whether he is asked not to repeat the same.

10. Appointment as Oath Commissioner when to be Cancelled.—If anOath Commissioner these rules or he is consistently found commitwhen to be -ting mistakes, the action for his removal from oath commissioner shall be taken.

11. *Consignment.*— (i) When the term of appointment of an Oath Commissioner expires and he is not appointed for any further term, he/she shall deposit the register of affidavits with the Registrar General of the High Court, Registrar, Administrative Tribunal, District and Sessions Judge or Senior most Civil Judge in the sub-divisional headquarters (where he was appointed as oath commissioner).

(ii) In case of sub-divisional head quarters the concerned Civil Judge shall get the registers consigned to the Record Room.

12. *Interpretation.*—In case of any doubt as to interpretation of these rules, or their application, the matter shall be referred to the Chief Justice whose decision in the matter shall be final.

13. *Residuary Powers.*—Nothing in these rules shall be deemed to affect the powers of the High Court to make such orders from time to time as it may deem fit in regard to all matters forming part of these rules and/or all matters incidental or ancilliary thereto not specifically provided for herein above.

14. *Repeal and Savings.*—The Himachal Pradesh Oath Commissioner (Appointment & Control) Rules, 1996 shall stand repealed on and with effect from the date these rules come into force.

By order,
(DHARAM CHAND CHAUDHARY)
Registrar (Rules).

Appendix -'A'

(a) Date of enrolment as an Advocate.
(b) Standing at the Bar:
(c) Monthly income of the applicant:
    (i) From his profession
    (ii) From other sources including income of his parents if living jointly:
(d) Whether the applicant has ever been appointed before as Oath Commissioner, if so, the period and the place:
(e) Whether the applicant is an ex-serviceman, SC/ST/OBC candidate ?

Date: *Signature*

Appendix-'B'

Certified that this affidavit has been read over and explained in vernacular/English to Shri_____ deponent, who seemed to have perfectly understood the same at the time of making thereof.

Oath Commissioner,
*Strike out which is not applicable.

Appendix-'C'

Deponent is identified by Sh._____whose signatures are given below.

Signature of the identifier (with date)

Signature of the Oath Commissioner (with date)

Appendix-'D'

Certified that the above was declared on oath/solemn affirmation before me at _____this day of _____200 by Shri/Smt._____deponent, who is personally known to me/identified by Sh._____who is personally known to me.

Oath Commissioner
Date
Time.

Appendix-'E'

Counter Foil.
No._____
Received Rs._____from
Shri/Smt._____R/o____
Teh._____Distt._____
Deponent on account of attestation of affidavit, this_____ day of ____200 at_____

Oath Commissioner

Receipt Form
No._____
Received Rs._____from
Shri/Smt._____R/o_____
Teh._____Distt._____
Deponent on account of attestation of affidavit, this____day of_____ 200 at_____

Oath Commissioner

Appendix-'F'

Sr. No.	Date and time of tender of affidavit for attestation.	Name and address of the person tendering affidavit.	Nature of affidavit briefly stated; if the affidavit relates to a cause in court, the cause should be specified.	Details of exhibits if any attached to the affidavit	Nature of the court or office in which the affidavit is intended to be filed.	Date and time of administering oath or affirmation	Name and address of witness(s) identifying the deponent if he is not known to the oath commissioner and his signature or thumb impression	Signature of the deponent.	Signature of oath Commissioner one
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th August, 2007

No. HHC/Admn.6(22)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under Section 9(5) of the Code of Criminal Procedure is pleased to empower the Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo to look after the urgent work pertaining to the court of District and Sessions Judge, Kinnaur with immediate effect till Sh. Ravinder Parkash, District & Sessions Judge, Kinnaur returns from medical leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

———

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Ms. Bhawna Thakur, Advocate as Oath Commissioner at Shimla, H.P., made vide Notification No.HHC/Admn.16(13)74-VI-19641-49 dated 16.9.2005, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA.

NOTIFICATION

Shimla, 9th August, 2007

No.HHC/GAZ/14-77/76-IV.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 11 days earned leave w.e.f. 18.72007 to 28.7.2007 with permission to Suffix Sunday fell on 29.7.2007 in favour of Shri V.K.Gupta, Registrar (Vigilance), High Court of H.P.Shimla.

Certified that Shri Gupta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Gupta would have continued to hold the post of Registrar (Vigilance), High Court of H.P., Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th August, 2007

No.HHC/Admn.16(13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(v) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 1996 is pleased to appoint Miss Sushma Bhardwaj, Advocate, Rohru, as Oath Commissioner at Rohru, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th August, 2007

No.HHC/Admn.6(24)74-VIII.—In partial modification of this Registry Notification No. HHC/ Admn.6(24)74-VII-14495-14505, dated 27.6.2007, the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, is pleased to appoint Civil Judge(Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur as Additional Chief Judicial Magistrate for

Bilaspur District enabling him to look after the urgent work pertaining to the court of Chief Judicial Magistrate, Bilaspur with immediate effect till Dr. Baldev Singh, Chief Judicial Magistrate, Bilaspur returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Sh. Vikas Negi, Advocate as Oath Commissioner at Rampur Bushehar, H.P., made vide Notification No.HHC/Admn.16(18)96-19660-67 dated 16-9-2005, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the August 20, 2007

No.HHC/GAZ/14-131/82-IV.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 5 days earned leave w.e.f. 21.8.2007 to 25.7.2007 with permission to suffix Sunday falling on 26.8.2007 in favour of Shri K.L.Sharma, District and Sessions Judge, Nahan.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Nahan, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2007

No.HHC/Admn.16 (7)74-IX.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(v) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 1996 is pleased to appoint Sh. Krishan Mohan, Advocate, Jawali, H.P., as Oath Commissioner at Jawali, for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla the 23rd August, 2007

No.HHC/Admn. 6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Jr.Divn.)-cum-JMIC(III),Una as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Jr. Divn.)-Cum-JMIC (II), Una and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" during the leave period of Ms. Abira Basu, with effect from with effect from 1.10.2007 to 12.10.2007 with permission to prefix Sunday falling on 30.9.2007 and to suffix Second Saturday and Sunday and Dussehra holidays with effect from 13.10.2007 to 21.10.2007 or until she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 23rd August, 2007

No.HHC/GAZ/14-265/2003.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 12 days earned leave with effect from 1.10.2007 to 12.10.2007 with permission to prefix Sunday falling on 30.9.2007 and to suffix Second Saturday and Sunday and Dussehra holidays with effect from 13.10.2007 to 21.10.2007 in favour of Ms. Abira Basu, Civil Judge (Jr.Division)-Cum-JMIC, (II), Una H.P.

Certified that Ms. Abira Basu is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Abira Basu would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr.Division)-Cum-JMIC (II), Una, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 24th August, 2007

No.HHC/GAZ/14- 38/74-V.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 6 days earned leave w.e.f. 29.8.2007 to 3.9.2007 with permission to prefix gazetted holiday falling on 28.8.2007 and to suffix gazetted holiday falling on 4.9.2007 in favour of Smt. Aruna Kapoor, Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Smt. Aruna Kapoor is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Aruna Kapoor would have continued to hold the post of Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the August 25th, 2007

No.HHC/GAZ/229/96-I.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 4 days commuted leave w.e.f. 6.8.2007 to 9.8.2007 in favour of Shri B.R.Chandel, District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri B.R.Chandel has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri B.R.Chandel would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADES AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (24)75-III.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(v) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 1996 is pleased to appoint Sh. Vijay Kumar, Advocate, Una, as Oath Commissioner at Una, H.P. for a period of two years, with effect from 1.9.2007, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 31st August, 2007

No.HHC/GAZ/14-255/2002.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 5 days commuted leave w.e.f. 16.8.2007 to 20.8.2007 in favour of Ms. Kanta Verma, Civil Judge (Junior Division.)-Cum-JMIC, (II), Mandi, H.P.

Certified that Ms.Kanta Verma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Kanta Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-Cum-JMIC (II), Mandi, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, August 31, 2007

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Addl.District and Sessions Judge(I),Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III & IV establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014- Administration of Justice" during the absence/ casual leave period of Shri B.R.Chandel, District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala w.e.f. 31.8.2007 to 4.9.2007.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (34)89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(v) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 1996 is pleased to appoint Sh. Manohar Singh, Advocate, Chamba, as Oath Commissioner at Chamba for a period of two years with immediate effect , for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (7)74-IX.— Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Sh. Avinash Singh Rana, Advocate as Oath Commissioner at Nurpur, H.P., made vide Notification No.HHC/Admn.16(7)74-VIII 3979-87 dated 5.3.2007, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2007

No.HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 is pleased to appoint Sh. Partap Singh , Advocate Rampur Bushehar, as Oath Commissioner at Rampur Bushehar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित